जसबीर सिंह और रामेश्वर सिंह मलिक से पहले जे.जे.

वरिष्ठ नागरिक मंच (पंजीकृत)-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

और अन्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपीनं. 2011 का 2171

03 अक्टूबर 2012

भारत का संविधान, 1950 - कला, 226/22 7 - रिट क्षेत्राधिकार - रेस-जुडिकाटा -हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 - एस. 79 - स्कूल के निर्माण के लिए इसे आवंटित करके खुली जगह/पार्क का रूपांतरण - 1978 में भूमि का अधिग्रहण किया गया नियोजित विकास - 1994 में स्कूल स्थल आवंटित किया गया - भूमि कभी भी पार्क के लिए नहीं बल्कि प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित की गई - याचिकाकर्ता ने मंदिर का निर्माण करके विवादित स्थल के हिस्से पर अतिक्रमण किया - बचाव में, मंदिर के उक्त क्षेत्र को स्कूल के पक्ष में किए गए आवंटन से छोड़ दिया गया - पहले एसएलपी, इस संबंध में रिट याचिकाओं और सिविल सूट पर पहले ही फैसला हो चुका है - याचिकाकर्ता ने अदालत से पहले की मुकदमेबाजी के तथ्यों को छुपाया - वर्तमान याचिका में कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग - माना गया, याचिकाकर्ता के मन में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है और उसने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है - रिट याचिका एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया।

माना गया कि उठाए गए प्रतिद्वंद्वी विवादों पर हमारे विचारशील विचार करने के बाद और वर्तमान मामले की अजीब तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि वर्तमान याचिका एक स्पष्ट (3) एआईआर 2010 एससी 2221 है

कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग. मामले के इस दृष्टिकोण में, तत्काल याचिका आगे दर्ज किए जा रहे कारणों के आधार पर लागत सहित खारिज किए जाने योग्य है।

(पैरा 10)

इसके अलावा, यह माना गया कि जिला नगर योजनाकार, फ़रीदाबाद द्वारा प्रशासक, हुडा, फ़रीदाबाद को भेजे गए दिनांक 8.3.1995 के ज्ञापन को पढ़ने से पता चलता है कि स्कूल स्थल पर अवैध अतिक्रमण सहित साइट पर होने वाली वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत होना, 0.63 एकड़ का क्षेत्र छोड़ दिया गया था, जिस पर कॉलोनी के निवासियों द्वारा अनधिकृत मंदिर का निर्माण किया गया है और शेष 1.5 एकड़ क्षेत्र को प्रतिवादी संख्या 4 को आवंटित किया गया था, जो लेआउट के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित था। सेक्टर 29, फ़रीदाबाद की योजना। यह भी नोट किया गया है कि कॉलोनी में अन्य पार्क/खुली जगह सामाजिक कार्यों, बच्चों के खेलने, व्यायाम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शाम/शाम की सैर के लिए मौजूद थे।

(पैरा 11)

इसके अलावा, यह माना गया कि उपरोक्त कई आदेशों को संयुक्त रूप से पढ़ने से, इसी कॉलोनी के विभिन्न निवासियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर की गई बार-बार की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, जिसमें एक ही उत्तरदाताओं के खिलाफ बिल्कुल समान राहत का दावा किया गया था, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान याचिका कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।

(पैरा 17)

इसके अलावा, यह तर्क भी उचित नहीं है कि याचिकाकर्ता को व्यक्तियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पहले दायर की गई और खारिज की गई कई रिट याचिकाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर करते समय इस संबंध में सुविधाजनक रूप से चुप्पी साध रखी है, जैसे कि वर्तमान याचिका उस समय की पहली

याचिका थी। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने भौतिक तथ्यों को छिपाकर इस न्यायालय तक पहुंचने का प्रयास किया है।

(पैरा 21)

इसके अलावा, यह माना गया कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर कई रिट याचिकाओं के साथ-साथ सिविल मुकदमे के बारे में, पूरी तरह से निर्दोष होने का परिचय देते हुए, इस न्यायालय के समक्ष तथ्यों को विकृत तरीके से पेश किया है। 'इस प्रकार, यह नि:संकोच माना जाता है कि याचिकाकर्ता

इस न्यायालय में साफ हाथों से संपर्क नहीं किया है। न तो कानून और न ही इक्विटी याचिकाकर्ता के पक्ष में है।

(पैरा 22)

याचिकाकर्ता के वकील ए. पी. भंडारी

गितीश भारद्वाज, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के वकील।

अश्वनी तलवार, प्रतिवादी नंबर 3 के वकील।

अक्षय भान के वकील आलोक मित्तल, प्रतिवादी नंबर 4 के वकील।

रमेश वार सिंह मलिक, जे.

(1) याचिकाकर्ता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत तत्काल याचिका के माध्यम से, परमादेश की प्रकृति में एक रिट की मांग कर रहा है, जिसमें उत्तरदाताओं को सामने स्थित खुली जगह/पार्क के उपयोग में बदलाव न करने का निर्देश दिया जाए। सेक्टर 29, फ़रीदाबाद में एचआईजी ब्लॉक के घर। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं को मूल योजना के साथ छेड़छाड़ न करने का निर्देश देने की मांग की है, जिसमें संबंधित क्षेत्र को खुली जगह/पार्क के रूप में दिखाया गया था, जिसे स्कूल के निर्माण के लिए बदलने की मांग की जा रही थी।

(2) प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था और उसके अनुसार, संपदा अधिकारी, हुडा, फरीदाबाद का लिखित बयान उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 की ओर से दायर किया गया था।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से हलफनामे के माध्यम से एक अलग उत्तर दायर किया गया था।

.

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड-प्रतिवादी संख्या 3 ने वर्ष 1980 में एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें सेक्टर 29, फरीदाबाद में एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी श्रेणियों में घरों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ऊपर उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के तहत मकान पात्र व्यक्तियों को आवंटित किए गए थे। हालाँकि, याचिकाकर्ता केवल एच आईजी श्रेणी से चिंतित है। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा जारी ब्रोशर के अनुसार, निवासियों के उपयोग के लिए पानी, सीवरेज, बिजली और पार्क/खुली जगह आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी थीं।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि उत्तरदाताओं के पास प्रतिवादी संख्या 4 को उक्त खुली जगह को अवैध रूप से आवंटित करके स्कूल स्थापित करने के लिए खुली जगह का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि खुली जगह को स्कूल में परिवर्तित करना प्रतिकूल होगा

याचिकाकर्ता का हित, जिसके सदस्य आस-पास रहते हैं। वह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 की धारा 79 (संक्षेप में 'हुडा अधिनियम') पर भी भरोसा करते हैं, यह तर्क देने के लिए कि उत्तरदाता खुली जगह/पार्क को में परिवर्तित करके हुडा अधिनियम की धारा 79 के तहत निहित कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे। स्कूल। अपने तर्कों को प्रमाणित करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, वीरेंद्र गौड़ और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, सिविल (अपील) संख्या 9151, 1994, 24.11 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। .1994.

(5) अंत में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जा सकता है और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जा सकता है कि वे खुली जगह/पार्क को स्कूल में परिवर्तित न करें।

(6) इसके विपरीत, उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील ने अपने उत्तर में ली गई प्रारंभिक दलीलों का जिक्र करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता फोरम ने साफ हाथों से इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया है और तत्काल याचिका खारिज की जा सकती है। केवल इसी कारण से भारी लागत। उन्होंने आगे कहा कि विचाराधीन भूमि स्कूल स्थल के लिए आरक्षित थी, न कि पार्क के लिए, जैसा कि याचिकाकर्ता ने गलत आरोप लगाया है। वास्तव में, याचिकाकर्ता उक्त भूमि के उस हिस्से पर अपना अवैध अतिक्रमण बनाए रखना चाहता है, जो एक स्कूल स्थल था। याचिकाकर्ता से कई बार संबंधित भूमि पर अपना अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया, लेकिन उसे नहीं हटाया गया।

(7) सेक्टर 29, फ़रीदाबाद के नियोजित विकास के लिए अवार्ड संख्या 6 दिनांक 30.3.1978 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। दिनांक 28.12.1994 (अनुलग्नक आर-1) के आदेश के तहत प्रतिवादी संख्या 4 को स्कूल स्थल आवंटित किया गया था। विचाराधीन भूमि कभी भी किसी पार्क के लिए आरक्षित नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत, यह प्राथमिक विद्यालय स्थल के लिए आरक्षित थी। आगे यह तर्क दिया गया कि यद्यपि प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित भूमि लगभग 2 एकड़ थी, फिर भी इस विद्यालय स्थल के कुछ हिस्से पर, कॉलोनी के निवासियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए एक अनधिकृत मंदिर का निर्माण किया गया था, प्रतिवादी अधिकारियों ने इसे उचित समझा। पार्क के लिए 0.63 एकड़ जमीन छोड़ें, जिसमें अनधिकृत मंदिर का निर्माण किया गया है। शेष 1.5 एकड़ क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। कॉलोनी के लेआउट प्लान से यह भी स्पष्ट था कि सामाजिक कार्यों, खेल-कूद, व्यायाम आदि के लिए अन्य पार्क और खुली जगह मौजूद हैं।

और कॉलोनी में वरिष्ठ नागरिकों की सुबह/शाम की सैर के लिए। उत्तरदाताओं क्रमांक 1 और 2 के विद्वान वकील इस संबंध में दिनांक 8.3.1995 (अनुलग्नक आर-2) के संचार का हवाला देते हुए कहते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत का निवारण वर्ष 995 में पहले ही कर दिया गया था।

(8) उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान याचिका एक तुच्छ याचिका है, इसी कॉलोनी के निवासियों द्वारा उठाए गए विवाद को पहले ही विभिन्न रिट याचिकाओं में बिना किसी सार के निपटाया जा चुका है और पाया गया है। और सिविल मुकदमा भी, जिसके कारण वर्तमान याचिका अनुकरणीय लागत के साथ खारिज होने योग्य है।

(9) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(10) उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर हमारे विचारशील विचार करने के बाद और वर्तमान मामले की अजीब तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि वर्तमान याचिका कानून की प्रक्रिया का एक स्पष्ट दुरुपयोग है। मामले के इस दृष्टिकोण में, तत्काल याचिका आगे दर्ज किए जा रहे कारणों के आधार पर लागत सहित खारिज किए जाने योग्य है।

(11) जिला नगर योजनाकार, फ़रीदाबाद द्वारा प्रशासक हुडा, फ़रीदाबाद को भेजे गए दिनांक 8.3.1995 के ज्ञापन को पढ़ने से पता चलता है कि स्कूल स्थल पर अवैध अतिक्रमण सहित स्थल पर होने वाली वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहना 0.63 एकड़ का क्षेत्र छोड़ दिया गया था, जिस पर कॉलोनी के निवासियों द्वारा अनधिकृत मंदिर का निर्माण किया गया है और शेष 1.5 एकड़ क्षेत्र को प्रतिवादी नंबर 4 को आवंटित किया गया था, जो प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित था, जैसा कि अनुसार सेक्टर 29, फ़रीदाबाद का लेआउट प्लान। यह भी ध्यान दिया गया है कि कॉलोनी में सामाजिक कार्यों, बच्चों के खेलने, व्यायाम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुबह/शाम की सैर के लिए अन्य पार्क/खुली जगह मौजूद थी।

(12) हालाँकि, ऐसा लगता है कि कॉलोनी के निवासी अभी भी संतुष्ट नहीं थे। स्कूल के आवंटन को रद्द करने के लिए हाउस नंबर 951-ए, एचआईजी, सेक्टर 29, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, फरीदाबाद के निवासी शांति प्रसाद ने इस न्यायालय के समक्ष 1995 की एक सिविल रिट

याचिका संख्या 13 748 दायर की थी। प्रतिवादी नंबर 4 के पक्ष में साइट, यह दावा करते हुए कि उक्त भूमि पार्क के लिए है। प्रस्ताव की सूचना जारी की गई और पार्टियां
अपने-अपने जवाब दाखिल किए। पक्षों को सुनने और कोई योग्यता नहीं पाए जाने के बाद, रिट याचिका को इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने दिनांक 29.1.1996 के आदेश के तहत खारिज कर दिया।

(13) 1995 की एक और सिविल रिट याचिका संख्या 14472, हाउस नंबर 873-ए, एचआईजी-आई1, सेक्टर 29, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, फरीदाबाद के निवासी कुलदीप सिंह राजपूत द्वारा दायर की गई थी, जो कि बिल्कुल सही थी। वही मुद्दा, जो याचिकाकर्ता ने मौजूदा याचिका में उठाया है। यहां सभी चार उत्तरदाताओं को 1995 के उपरोक्त सीडब्ल्यूपी संख्या 14472 में भी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था और बिल्कुल उसी राहत का दावा किया गया था। रिट याचिका को इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने आदेश दिनांक 6.3.1996 (अनुलग्नक आर-4) के तहत खारिज कर दिया था, और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: -

"1995 की सिविल रिट याचिका जे3 748 जिसमें वही राहत का दावा किया गया है जो यहां मांगी गई है, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा 29.1.1996 को पहले ही खारिज कर दी गई है। मामले को देखते हुए, इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती, जिसे परिणामस्वरूप खारिज कर दिया गया है। " 6.3.1996

(14) सिविल सूट नंबर 452 के रूप में स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए एक मुकदमा, श्री सनातन धर्म मंदिर सभा के नाम से एक पंजीकृत निकाय द्वारा, फरीदाबाद में विद्वान सिविल कोर्ट के समक्ष दायर किया गया था। रजि.), राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी और अन्य के खिलाफ। सिविल मुकदमे में भी बिल्कुल यही राहत मांगी गई थी। विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फरीदाबाद ने अन्य बातों के अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादी समाज द्वारा दायर रिट याचिका को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया था, सिविल सूट को भी लागत के साथ खारिज कर दिया

गया था, निर्णय दिनांक 20.2 द्वारा .2010 (अनुलग्नक आर-5)। विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), फ़रीदाबाद के उपरोक्त निर्णय को, विद्वान जिला न्यायाधीश, फ़रीदाबाद के समक्ष सिविल अपील संख्या 90/20.4.10 में चुनौती दी गई, लेकिन आदेश दिनांक के तहत इसे वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। 4.01.2011 (अनुलग्नक आर-6)।

(15) 2005 का एक और सीडब्ल्यूपी नंबर 12458 इसी कॉलोनी के निवासियों द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने वर्तमान सोसायटी की तरह ही एक सोसायटी का गठन किया है। 2005 का उपर्युक्त सीडब्ल्यूपी नंबर 12458 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा वर्तमान उत्तरदाताओं के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें प्रतिवादी नंबर 4 के पक्ष में स्कूल साइट के आवंटन को चुनौती दी गई थी। यह

रिट याचिका को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा भी खारिज कर दिया गया था, वीआईडीसी आदेश दिनांक 11.8.2005 और इसे undcr के रूप में पढ़ा जाता है: -

"चूंकि रिट याचिका बुरी तरह से देरी और देरी से ग्रस्त है, हालांकि याचिकाकर्ता ने, माना कि, वर्ष 1995 में प्रतिवादी नंबर 4 को भूखंड के आवंटन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, यहां तक कि वर्ष 2002 में भी, हम इसके इच्छुक नहीं हैं इस समय रिट याचिका पर विचार करें। बर्खास्त. "

(16) यहां यह भी ध्यान रखना उचित है कि सीडब्ल्यूपीएनओ के माध्यम से इस न्यायालय से संपर्क करने से पहले। 2005 का 12458, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 523/2004, (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसे वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता को सलाह दिए जाने पर संविधान की धारा 226 के तहत याचिका दायर करके इस न्यायालय से संपर्क करने की अनुमति देते हुए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 523/2004 में पारित यह आदेश दिनांक 27.9.2004 को अंडरसीआर के रूप में पढ़ा जाता है:-

“वकील को सुनने के बाद अदालत ने निम्नलिखित कहा

आदेश

याचिकाकर्ता को इस याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाती है और यदि सलाह दी जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

तदनुसार, रिट याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

27.9.2004.

(17) इसी कॉलोनी के विभिन्न निवासियों और रेजिडेंट वेई फेयर एसोसिएशन द्वारा दायर की गई बार-बार की रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, एक ही उत्तरदाताओं के खिलाफ बिल्कुल समान राहत का दावा करते हुए, उपरोक्त कई आदेशों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान याचिका कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।

(18) हमने याचिकाकर्ता फोरम की ओर से उठाए गए तर्कों पर विचार किया है और पाया है कि उनमें कोई दम नहीं है। वर्तमान मामले में हुडा अधिनियम की धारा 79 बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। वीरेंद्र गौड़ के मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने फैसले पर भरोसा किया (सुप्रा), याचिकाकर्ता के लिए कोई मददगार नहीं है क्योंकि यह तथ्यों पर स्पष्ट रूप से भिन्न है। वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। प्रश्नाधीन भूमि विद्यालय स्थल के लिए आरक्षित की गई है, जो लेआउट प्लान से स्पष्ट है।

(19) यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि किसी भी संहिताबद्ध या निर्णयित कानून को लागू करने से पहले प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखा जाना चाहिए। कभी-कभी, एक शब्द का अंतर भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। वर्तमान मामले की दी गई तथ्यात्मक स्थिति में, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि याचिकाकर्ता फोरम के मन में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। याचिकाकर्ता को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसके पड़ोसियों या इसी तरह के किसी अन्य वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर की

गई पिछली याचिकाएं याचिकाकर्ता पर बाध्यकारी नहीं होंगी। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए, तो कॉलोनी का प्रत्येक निवासी एक या दूसरे के समक्ष इसी तरह का मुकदमा लड़ रहा होगा और यह एक कभी न खत्म होने वाला मुकदमा होगा।

(20) एक समान स्थिति में, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने, 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 20269 (मान सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) का फैसला करते हुए, दिनांक 9.8.2012 के आदेश के तहत, अंडरसीआर के रूप में रखा: -

"स्कूल की साइट एनेक्सचर पी.आई. के ले-आउट प्लान-13 में दिखाई गई है। याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि यदि ऐसे स्कूल को एनेक्सचर पी1 के प्लान-ए के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है, तो याचिकाकर्ता के घर के पीछे और याचिकाकर्ता के घर के पीछे के बीच की खुली जगह स्कूल की साइट उपलब्ध होगी। सुनवाई की आखिरी तारीख यानी 3.8.2012 को, पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

"हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने स्वीकार किया कि वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर याचिकाकर्ताओं के पड़ोसियों द्वारा 2008 की पिछली सिविल रिट याचिका संख्या 2560 में फैसला सुनाया गया है, जिस पर 25.3.3 को निर्णय लिया गया था। .2010, लेकिन यह कहा गया है कि यदि स्कूल का स्थान अनुलग्नक पी1 की योजना-13 में दिखाए गए अनुसार योजना-ए में दिखाए गए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इससे किसी भी व्यक्ति के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि खुली जगह मिल जाएगी। याचिकाकर्ता को उसी क्रम में अन्य आवंटियों की तरह। सुश्री मोगा और श्री शर्मा, निर्देश प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह का समय चाहते हैं। 9.8.2012 को सूची. ”

सुश्री मोंगा, विद्वान डीएजी, हरियाणा ने कहा है कि वास्तव में याचिकाकर्ता ने बिना अनुमति के अपने घर के पीछे एक गेट खोल दिया है और यही कारण है कि वह स्कूल की साइट को स्थानांतरित करने पर जोर दे रहा है, जिसका ले-आउट प्लान था वर्ष 2000 में अंतिम रूप

दिया गया। 2008 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2560 वाली पिछली रिट याचिका याचिकाकर्ता के दोनों पक्षों के निकटतम पड़ोसियों द्वारा दायर की गई थी।

उक्त रिट याचिका 25.3.2010 को खारिज कर दी गई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद, वर्तमान रिट याचिका 8.1T2010 को दायर की गई है।

उक्त तथ्य के मद्देनजर, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पड़ोसियों द्वारा समान मुद्दों को उठाने वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता को उन्हीं मुद्दों पर इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का दोबारा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नतीजतन, वर्तमान रिट याचिका रुपये के जुर्माने के साथ खारिज की जाती है। 1.00 लाख (एक लाख रुपये), जो एक महीने के भीतर हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा।"

(1) यह इस कारण से भी अपील नहीं करता है कि याचिकाकर्ता को व्यक्तियों और रेजिडेंट वेई किराया एसोसिएशन की ओर से पहले दायर की गई और खारिज की गई कई रिट याचिकाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर करते समय इस संबंध में सुविधाजनक रूप से चुप्पी साध रखी है, जैसे कि वर्तमान याचिका उस समय की पहली याचिका थी। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने भौतिक तथ्यों को छिपाकर इस न्यायालय तक पहुंचने का प्रयास किया है।

(2) याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर कई रिट याचिकाओं के साथ-साथ सिविल मुकदमे के बारे में, पूरी तरह से निर्दोष होने का परिचय देते हुए, इस न्यायालय के समक्ष तथ्यों को विकृत तरीके से पेश किया है। इस प्रकार, यह निःसंकोच माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने साफ हाथों से इस न्यायालय का रुख नहीं किया है। न तो कानून और न ही इक्विटी याचिकाकर्ता के पक्ष में है।

(3) ऊपर उल्लिखित वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ, हमारी राय है कि तत्काल रिट याचिका, किसी भी योग्यता से रहित और बिना किसी सार के, विफल होनी चाहिए।

मैसर्स मैजेस्टिक ऑटोकॉम्प प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वि. हरियाणा राज्य 1061

औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास

निगम लि. और दूसरे

(रामेश्वर सिंह मलिक, जे.)

परिणामस्वरूप, रिट याचिका को लागत सहित खारिज करने का आदेश दिया जाता है, जिसकी मात्रा '1,00,000/- (एक लाख रुपये) है। याचिकाकर्ता को लागत आज से तीन महीने की अवधि के भीतर हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा करानी होगी। यदि याचिकाकर्ता द्वारा तीन महीने की निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है, तो हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव, कानून के अनुसार, याचिकाकर्ता से लागत की राशि वसूल करने के लिए सक्षम होंगे।

<u>अस्वीकरण:</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी

(Trainee Judicial

Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा